3.4.4/2022-23/SBD/200/chapter in edited book

13 भूमि असमानता– सामाजिक, आर्थिक विषमता के परिप्रेक्ष्य में : एक विहंगावलोकन

डॉ सुभाष भिमराव दोंदे
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणे संलग्न,
किर्ती कॉलेज, दादर (प.) मुंबई

सारांश

एक तरफ विश्व की एक–चौथाई भूमि का अपक्षरण, लवणीकरण, अम्लीकरण और रासायनिक प्रदूषण के कारण अवक्रमण हो चुका है, जिसका पारिस्थिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है; तो दूसरी तरफ 1980 से पिछले चार दशकों में भूमि असमानता में लगातार बढ़ोतरी हुई है; जिसके कारण छोटे जोत वाली कृषि में शामिल अनुमानित 2.5 बिलियन सीमांत या अल्प भूधारक किसानों की आजीविका के लिए खतरा बना हुआ है। भूमी– एक गैर–नवीकरणीय संसाधन के स्वामित्व संकेंद्रण का यह एक अवांछित रूप है; जिसमे कृषि और भूमि क्षेत्र में बड़े उद्यम विकसित हो रहे हैं। उच्च आय वाले देशों में, बड़े खेत उत्तरोत्तर बड़े होते जा रहे है । सबसे बड़े 1 प्रतिशत फार्मों ने 70 प्रतिशत कृषि भूमि का संचालन किया है और कॉर्पोरेट खाद्य प्रणालियों की आपूर्ति की है । लगभग 84 प्रतिशत खेत दो हेक्टेयर से छोटे है, जिन्होंने लेकिन केवल 12 प्रतिशत कृषि भूमि का परिचालन किया है। अधिकांश निम्न–आय वाले देशों में औसत कृषि आकार के सिकुड़ने के पीछे छिपे हुए मेगा–फार्मों की बढ़ती संख्या है। भारत में विभिन्न भूमिधारक समूहों के बीच आय असमानता सांख्यिकीय तौर पर उद्‌बोधक है। एक अल्प भूधारक या सीमांत किसान परिवार की औसत वार्षिक आय दस हेक्टेयर से अधिक जोत वाले बड़े किसानों की तुलना मे साढ़े सात गुना कम पायी गयी हैं। विषमता के अन्य रूपों के साथ–साथ कई वैश्विक विपत्तियों और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, स्थानिक और पर्यावरणीय ऊंचनीच जैसे प्रवृत्तियों के लिए भूमि असमानता केंद्रीय है। इसलिये यदि मानवता को वैश्विक संधारणीयता, स्थिरता और सामाजिक न्याय की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति करनी है, तो भूमि असमानता पर कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है।

(कुंजी शब्दः भूमि अवक्रमण, भूमि असमानता, अल्प भूधारक, सन्धारणीयता, सामाजिक न्याय)

प्रस्तावना– अपक्षरण, लवणीकरण, संघनन (सईघन), अम्लीकरण और रासायनिक प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 33 प्रतिशत भूमि पहलेसे ही अत्यधिक निम्नीकृत है– जिसका क्षेत्र अफ्रीकी महाद्वीप के आकार समतुल्य है। भूमि निम्नीकरण पर्यावरण क्षरण तथा

Principal
D. E. Society's
Kirti M. Doongursee College
of Arts, Science & Commerce
Dadar (W), Mumbai - 28.

भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण बना है। स्वाभाविक रूप से गैर–नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद, बढ़ती जनसंख्या के परिपेक्ष्य में भूमि निम्नीकरण को अक्सर अनदेखा किया गया है। भूमि का जब वर्षों के बजाय दशकों और सदियों पर विचार किया जाता है, तो भूमि कुछ भी है– लेकिन स्थिर या स्थैतिक है और ना ही बढ़ने वाली है। किन्तु विभिन्न जैव–भौतिक प्रक्रियाओं, मानवजनित गतिविधियों और अर्थव्यवस्थाओं के परस्पर जटिल संबंधों की विशेषता है; जो समय के साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन को आकार देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संघटन (2016) के अनुसार दुनिया के अरबों सबसे गरीब व्यक्तियों में हर चार में से तीन के लिए कृषि भूमि महत्वपूर्ण है, जो अपने निर्वाह के लिए प्रत्यक्षतः कघषि या इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। आज दुनिया भर में कृषि श्रमिकों की संख्या काफी हद तक 30 साल पहले के समान है । दुनिया के गरीबों के लिए भूमि के अत्यधिक महत्व के बावजूद, हम इसके मूल्य और वितरण के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मौजूदा अनुमान न तो भूमि स्वामित्व असमानता को दर्शाते हैं और न ही मूल्य असमानता को दर्शाते हैं ।

अबतक भूमि की असमानता को ऐतिहासिक रूप से भूमि स्वामित्व में अंतर के रूप में मापा गया है। लेकिन यह बहुत अधिक जटिल और बहुआयामी है। 'भूमि असमानता पहल' की रिपोर्ट (2020) मे भूमि असमानता को देखने के लिए निम्नलिखित चार दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है:

1.भूमि का आकार और मूल्य जिस पर लोगों की पहुंच या धारण है।

2. भू–धृति धारक के स्वामित्व की सुरक्षा का स्तर जो लोगों के पास है।

3. भूमि पर निर्णय लेने की उनकी शक्ति सहित लोगों का वास्तविक नियंत्रण और

4. भूमि से होने वाले लाभों का नियंत्रण

विषमता के अन्य रूपों के साथ–साथ कई वैश्विक विपत्तियों और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, स्थानिक और पर्यावरणीय ऊंचनीच जैसे प्रवृत्तियों के लिए भूमि असमानता केंद्रीय है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत ग्रामीण आबादी कृषि भूमि मूल्य के 60 प्रतिशत पर कब्जा कर लेती है; निचला आधा केवल 3 प्रतिशत को नियंत्रित करता है। यह भूमि असमानता छोटे जोत वाली कृषि में शामिल अनुमानित 2.5 बिलियन लघु धारक लोगों की आजीविका के लिए खतरा बनी हुई है। 1980 के दशक से वैश्विक भूमि संकेंद्रण में लगातार वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज, दुनिया के सबसे बड़े 1 प्रतिशत खेत दुनिया के 70 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि का संचालन या परिचालन करते हैं। सामाजिक–आर्थिक विषमता के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन भूमि असमानता के कुछ पहलुओं को वैश्विक तथा भारत के संदर्भ में उजागर करता है।

परिकल्पना

गैर– नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भूमि का एक तिहाई हिस्सा प्रदूषण एवं अत्यधिक दोहन जैसे मानवजनित गत विधियों के कारण पहले से ही निम्नीकृत हो चुका है और बचे हुए भूमि के वितरण, स्वामित्व या अधिग्रहण में पूंजीपतियों तथा कॉरपोरेट सेक्टर के निवेश के कारण पराकोटि की असमानता है। वैश्विक सन्धारणीयता, स्थिरता और सामाजिक न्याय के परिपेक्ष्य में भूमि के वितरण, स्वामित्व या अधिग्रहण में सभी सामाजिक–आर्थिक वर्गों की साझेदारी निहायती जरूरी है।

क्रिया–विधि

प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय–वस्तु विश्लेषण के दायरे में असंरचित और गैर–संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं अनुसंधान कर्ताओं के संदर्भ सूचीबद्ध प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक अध्ययन है।

विचार–विमर्श

वैश्विक भूमि असमानता के पृष्ठभूमि में ध्रुवीकृत भूमि और कृषि–खाद्य प्रणाली का परस्पर संबंध

उजागर करती इस विस्तृत एवं आधुनिकतम 'भूमि असमानता पहल' रिपोर्ट (2020) के अनुसार, लैटिन अमेरिका दुनिया में भूमि असमानता के उच्चतम स्तर वाला क्षेत्र है, जिसमें शीर्ष 10 प्रतिशत ज़मींदार 75 प्रतिशत तक कृषि भूमि को नियंत्रित करते हैं और निम्न स्तर के 50 प्रतिशत 2 प्रतिशत से कम कृषि भूमि के मालिक हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, दक्षिण अफ्रीका में अत्यधिक भूमि संकेंद्रण दर्ज किया गया है, जहां केवल 0.28% खेतों में देश में कृषि उत्पादन के मूल्य का लगभग 80% उत्पादन करने का अनुमान है। दक्षिण अफ्रीका जैसा सबसे औद्योगिक और शहरीकृत देश– जो अभी भी अपनी वयस्क आबादी के लिए गैर–कृषि रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं है, जिससे उनमें से 30.1% बेरोजगार हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, यदि अफ्रीका में भूमि असमानता के मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया जाता है, तो यह एक टाइम बम साबित होगा। उन्होंने जोर दिया कि अगले 15 वर्षों में लगभग 375 मिलियन लोग अफ्रीका में कामकाजी या रोजगार–योग्य उम्र तक पहुंच जाएंगे – एक ऐसी आबादी जो आज के अमेरिका और कनाडा के संयुक्त आकार के बराबर है। किसी महाद्वीप या देश की अर्थव्यवस्था अपनी बढ़ती श्रम शक्ति को कैसे अवशोषित करेगी और विशेष रूप से युवा रोजगार से कैसे निपटेंगी? यह प्रश्न भूमि असमानता में वृद्धि और बृहत–कृषि विकास मॉडल के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है; जो पूंजी प्रधान, श्रम बलों को अवशोषित करने के बजाय मुक्ति या रिहाई दिलाने वाले और यहां तक कि श्रम बलों को विस्थापित करने वाले हैं।

शोधकर्ताओं ने पहले दर्ज की गयी तुलना में काफी अधिक भूमि असमानता पाई, उन्होंने कहा कि असमानता का वास्तविक स्तर और भी अधिक होने की संभावना है क्योंकि उन्होंने भूमि असमानता को मापने में कॉर्पोरेट स्वामित्व को ध्यान में नहीं रखा था। रिपोर्ट में कहा गया है, "कॉर्पोरेट संस्थाओं और निवेश फंडों के संचालन पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि विभिन्न देशों में बड़ी मात्रा में वे जमीन खरीद और नियंत्रित कर रहे हैं। यह स्वामित्व संकेंद्रण का एक अवांछित रूप है जो वर्तमान में सभी सर्वेक्षणों से पूरी तरह से चूक गया है, और इसकी मात्रा निर्धारित करना बहुत कठिन है; क्योंकि सभी निवेश फंड अपने निवेश के बारे में पारदर्शी नहीं हैं। और भले ही कंपनियां सीधे जमीन का अधिग्रहण नहीं कर रही हों, फिर भी वे जमीन को नियंत्रित कर सकती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से संविदात्मक व्यवस्थाओं और मूल्य श्रृंखलाओं पर नियंत्रण तथा के सभी वित्तीय साधनों के माध्यम से इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। भूमि को नियंत्रित करने और भूमि के लाभों को नियंत्रित करने के लिए आपको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। कृषि और भूमि क्षेत्र में बड़े उद्यम विकसित हो रहे हैं जो बीज, उत्पादन से लेकर खुदरा, कीटनाशकों से लेकर थाली तक पूरी मूल्य श्रृंखला को नियंत्रित कर रहे हैं। इसका भूमि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

भूमि के आकार और उत्पादन के मूल्य के मामले में मेगा–फार्मों के उद्भव या उत्थान के साथ सबसे छोटे और सबसे बड़े भूमिधारकों के बीच द्रुत गति से असमानता में वृध्दि हुई है। सबसे बड़ा खतरा कॉरपोरेट–नियंत्रित कृषि का विस्तार है, जो स्थानीय रूप से प्रधान व्यवस्था को अव्यवहारिक या अव्यवहार्य बना सकता है, जो लोगों को उनकी भूमि और आजीविका से विस्थापित कर सकता है, जिनके पास कोई सार्थक विकल्प नहीं है। अध्ययन ने पिछले 100 वर्षों में भूमि असमानता के रुझान या झुकाव को देखा तो इससे पता चलता है कि 20वीं सदी की शुरुआत से 1980 के दशक तक भूमि असमानता में लगातार कमी आई है। किन्तु फिर 1980 से प्रवृत्ति उलट गई; तब से भूमि असमानता लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़े एक प्रतिशत फार्मों ने 70 प्रतिशत कृषि भूमि का संचालन किया और कॉर्पोरेट खाद्य प्रणालियों की आपूर्ति की। लगभग 84 प्रतिशत खेत दो हेक्टेयर से छोटे थे, लेकिन उन्होंने केवल 12 प्रतिशत कृषि भूमि का परिचालन किया, जिसमें कॉर्पोरेट आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का बहुत कम अवसर था। अधिकांश निम्न–आय वाले देशों में एक स्पष्ट प्रवृत्ति या झुकाव खेतों की बढ़ती संख्या थी, जो छोटे खेतों के आकार के साथ संयुक्त थी। दुनिया भर में, और विशेष

रूप से उच्च आय वाले देशों में, बड़े खेत उत्तरोत्तर बड़े होते जा रहे थे। विश्व स्तर पर सबसे छोटे खेतों का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका और एशिया में था, जहां वे आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका के लिए आवश्यक थे। जहाँ अधिकांश खेत दो हेक्टेयर से छोटे थे, और 2–10 हेक्टेयर क्षेत्र के खेतों में सार्थक मात्रा में भूमि थी। रिपोर्ट में पाया गया कि भूमि का एक बहुतही छोटा अनुपात बहुत बड़े खेतों का हिस्सा प्रतीत होता है। अधिकांश निम्न–आय वाले देशों में औसत कृषि आकार के सिकुड़ने के पीछे छिपे हुए मेगा–फार्मों की बढ़ती संख्या थी, जिसमें हर एक का क्षेत्र हजारों हेक्टेयर था।

एशिया और अफ्रीका में भूमि असमानताएँ आनुपातिक तौर पर उच्च दर से बढ़ी हैं। एशिया के संदर्भ में, इस क्षेत्र की बढ़ती भूमि असमानता को 'एशियाई हरित क्रांति' से जोड़ा गया, जिसमें इन देशों ने उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई और उच्च उपज वाली फसलों की किस्मों के अपने उपयोग में विस्तार किया। इससे कृषि के अलावा खनन, बुनियादी ढांचे और पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हुआ; जिसकी वजह से भूमिहीनों की आबादी बढ़ी। जबकि एक क्षेत्र के रूप में एशिया में भूमि असमानता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, किन्तु चीन और व्हिएतनाम जैसे तथाकथित कम्युनिस्ट (साम्यवादी) समाजों ने असमानता के निम्नतम स्तर को देखा गया।

भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों में भूमि मूल्यों और भूमिहीन आबादी को शामिल करने पर असमानता का उच्चतम स्तर दिखाई देता है। आय तथा आर्थिक विषमता, हालांकि, इन देशों के लिए कृषि–संबंधी संकट को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है। भारत में शीर्ष एक प्रतिशत कमाई करने वालों ने देश में कुल आय का 22 प्रतिशत कब्जा कर लिया है । इस संदर्भ में एक अध्ययन में 1922 से 2014 तक खपत, सरकारी खातों और आयकर डेटा की छानबीन से पता चलता है आय असमानता में लगातार वृद्धि हुई है।

भारत में विभिन्न भूमिधारक समूहों के बीच आय असमानता सांख्यिकीय तौर पर उद्‌बोधक है। किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी दलवाई समिति के अनुसार, 2015–16 में एक छोटे और सीमांत किसान परिवार की औसत वार्षिक आय 79,779 रुपये थी। अब इसकी तुलना दस हेक्टेयर से अधिक जोत वाले बड़े किसानों की आय से करें। ऐसे किसान एक छोटे और सीमांत किसान की तुलना में साढ़े सात गुना अधिक कमाते हैं, या विशिष्ट रूप से प्रत्येक वर्ष 605,393 रुपये कमाते हैं। एक मध्यम और अर्ध–मध्यम किसान के परिवार ने एक छोटे और सीमांत किसान के परिवार की तुलना में 201,083 रुपये या ढाई गुना अधिक कमाई की। इसका मतलब है कि 85 प्रतिशत किसान परिवार कुल आय का 9 प्रतिशत कमाते हैं जबकि शेष 91 प्रतिशत कमाते हैं। यदि आप इसकी तुलना भारत में समग्र असमानता से करते हैं, तो यह बहुत अधिक है।

कृषि सुधारों का प्रारंभिक वादा भूमिहीनों को भूमि वितरित करना और काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना था। हालाँकि, दुर्भाग्य से, भारत के कृषि सुधारों ने कृषि समुदाय में समतावाद सुनिश्चित नहीं किया, दलवई समिति की रिपोर्ट कहती है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के तरीके तैयार करते हुए कृषि नीतियों को इस पहलू पर ध्यान देने के लिए कहा गया है, जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के अनुसंधानकर्ताओं के शोध पत्र के अनुसार, पंजाब में खेती से मासिक प्रति व्यक्ति आय 2,311 रुपये थी जबकि पश्चिम बंगाल में यह सिर्फ 250 रुपये थी। यह अंतर नौ गुना है। इससे भी अधिक, देश के तीन सबसे बड़े राज्यों– पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में मासिक व्यय आय से अधिक हो गया और तदनुसार, एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवारों की औसत आय खपत से कम थी।

खेती से होने वाली आय का निर्धारण करने में भूमि का कब्जा प्रमुख परिवर्ती था, जो अर्ध आय असमानता के लिए जिम्मेदार था, और इसलिए आय असमानता को समझाने में महत्वपूर्ण परिवर्ती था। 0.5 हेक्टेयर भूमि धारक किसान अपने खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं करते हैं। यह

एक प्रासंगिक मुद्दा उठाता है जिसका नीतिगत प्रभाव पड़ता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने उत्पादकता और उपज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन तब से भूमि जोत काफी विखंडित हो गई है। पिछले 40 वर्षों में सीमांत भूमि जोत तीन गुना हो गई है। इसका मतलब है कि पुरानी रणनीति समान उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है।

किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के संदर्भ में यह पहलू महत्वपूर्ण है। बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए, 2003–13 के दौरान, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार आय को दोगुना करने में सक्षम हुए हैं। लेकिन एक छोटा किसान जिसके पास एक हेक्टेयर तक की जमीन है, उसी समय के दौरान आय में केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आय समूह–विशिष्ट रणनीति लागू करनी होगी। और देश की विशाल छोटे किसानों की आबादी को दोहराने के लिए: भारत में कुल जोत का 67 प्रतिशत का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है। खेती को आकर्षक बनाने की चुनौती अभी और कठिन होती गई। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी खर्च में अकर्मण्यता या ठहराव के कारण गैर–कृषि रोजगार निर्माण में कमी आई है। इसलिए, अधिकांश छोटे और सीमांत किसान, जो खेती से ज्यादा कमाई नहीं करते हैं, वे आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह लौकिक खतरे की घंटी बजाता है।

उपसंहार

भूमि असमानता पहले के अनुमान से अधिक है, और यह कई वैश्विक चुनौतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे संबोधित करने के साधनों को कमजोर रूप से लागू किया गया है क्योंकि वर्तमान भूमि वितरण पैटर्न में ताकतवरों का निहित स्वार्थ छुपा हुआ है। क्षैतिज असमानता, जो लोगों के विशिष्ट समूहों में लिंग, नृजातियता (नस्ल) या संस्कृति पर आधारित विषमता है, भूमि की पहुंच, स्वामित्व और नियंत्रण से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की असमानता संवहनीयता या संधारणीयता का अवमूल्यन करते हुये दुर्बल करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं, देशज लोग और स्थानीय समुदाय पारिवारिक कल्याण, संधारणीय आजीविका, जैव विविधता संरक्षण, जैव–सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय के अभिरक्षक होते हैं। इस प्रकार भूमि असमानता को बढ़ने से रोकना मानवता के साझा हित में है। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए एक व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता होगी, जिसमें सभी स्तरों पर राज्य संस्थानों, दाताओं और विकास भागीदारों, निजी क्षेत्र और लोगों के संगठनों, किसानों और भूमि से अपना जीवन यापन करने वाले सभी शामिल होने की आवश्यकता है। यदि मानवता को वैश्विक संधारणीयता, स्थिरता और सामाजिक न्याय की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति करनी है, तो भूमि असमानता पर कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Anseeuw, W., & Baldinelli, G. M. (2020).Uneven ground: Land inequality at the heart of unequal societies. https://www.landcoalition.org/en/uneven-ground/
2. Bauluz Luis, Govind Yajna, & Novokmet Filip (2020) Global Land Inequality World Inequality Lab
3. Chacko Susan (2020) Land inequality threatens livelihood of 2.5 bln: Report www.dowtoearth.com https://www.google.com/amp/s/www.downtoearth.org.in/news/agriculture/amp/land-inequality-threatens-livelihood-of-2-5-bln-report-74418
4. Chaturvedi Sumit (2016) Land Reforms Fail; 5% of India's Farmers Control 32% Land www.indiaspend.com https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/agriculture/land-reforms-fail-5-of-indias-farmers-control-32-land/amp
5. Jong Hans Nicholas (2020) Land inequality is worsening and fueling other social ills, report says. www.mongabay.comhttps://www.google.com/amp/s/news.mongabay.com/2020/12/land-inequality-international-coalition-oxfam-report/amp
6. Mahapatra Richard (2018) Only 15% landholders earn 91% of total national income www.dowtoearth.com